Theory of Bank Rate (6)

Increase in the Importance of the Bank Rate :-

विभिन्न देशों के केन्द्रीय बैंक अपनी बैंक-दर में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, सितम्बर, 1951 ई० में बैंक ऑफ इंगलैण्ड की बैंक-दर को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 2½ प्रतिशत तथा नवम्बर, 1951 ई० में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने अपनी बैंक-दर को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 3½ प्रतिशत कर दिया। बैंक ऑफ इंगलैंड की बैंक-दर में इस वृद्धि के कई कारण थे, किन्तु इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण इंगलैंड के भुगतान-संतुलन को संतुलित करना तथा मुद्रा-स्फीति के दबाव को कम करना था।

1956-57 एवं 1957-58 में विश्व के अधिकांश उन्नत देशों में आर्थिक नियंत्रण के लिए बैंक-दर में परिवर्तन किया गया। अधिकांश देशों में बैंक-दर में वृद्धि की गयी। उदाहरण के लिए, 16 मई 1957 को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने अपनी बैंक-दर 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया। बैंक-दर में इस वृद्धि के कई कारण थे जिनमें निम्नलिखित विशेषरूप से महत्वपूर्ण थे :—

(i) मुद्रा-स्फीति के दबाव को रोकना।
(ii) विनियोग के प्रसार को सीमित बनाना।
(iii) अन्तर्राष्ट्रीय शोधन तुला में संतुलन स्थापित करना।

Scanned with CamScanner

8 मार्च, 1962 ई० को बैंक ऑफ इंगलैंड ने अपनी बैंक-दर को पुनः 6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया। इसका प्रधान कारण यह बतलाया गया कि इससे पूर्व इंगलैंड की बैंक-दर जापान के अतिरिक्त अन्य सभी प्रमुख देशों के केन्द्रीय बैंक की बैंक-दर से अधिक थी। पुनः 21 मार्च मार्च, 1962 को बैंक ऑफ इंगलैंड ने अपनी बैंक-दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर साढ़े 5 प्रतिशत कर दिया। इसी प्रकार 3 जनवरी, 1963 ई० को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने अपनी बैंक-दर को चार प्रतिशत से बढ़ाकर साढ़े 4 प्रतिशत कर दिया। 8 जनवरी, 1971 ई० को बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए भारत-संतुलन के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने अपनी बैंक-दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया। अंत में 30 मई, 1973 ई० को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने देश में मुद्रा-स्फीति को बढ़ते हुए दबाव को रोकने के लिए बैंक-दर को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया। पुनः 23 जुलाई, 1974 ई० को इसने बैंक-दर को 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया। इससे पूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की बैंक-दर इतनी अधिक कभी नहीं थी। इससे स्पष्ट है कि बैंक-दर पुनः बढ़ने लगी। वास्तव में अधिकांश विकसित अर्थ-व्यवस्था वाले देशों में बैंक-दर पुनः मौद्रिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन बन रही है। किंतु, आज भी

इसकी सफलता के मार्ग में विभिन्न बाधाएँ हैं जिससे यह प्राचीन महत्व को नहीं प्राप्त कर सकता है।

अर्द्ध-विकसित देशों में निम्नलिखित कारणों से बैंक-दर नीति के मार्ग में सफल हो नहीं हो पा रही :-

(1) अविकसित देशों में मुद्रा-बाजार तथा पूँजी-बाजार में उचित सामंजस्य का अभाव पाया जाता है।

(2) इन देशों में व्यापारिक बिलों का बहुत ही कम प्रचार रहता है

(3) इन देशों में बैंकिंग एवं साख-सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार भी कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहता है।

(4) इन देशों में बैंक की कोषों की माँग भी कम रहती है।

फिर भी अधिकांश अविकसित राष्ट्रों की स्थिति में अब धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। इन देशों में भी बिल बाजार को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, बैंकिंग सम्बन्धी सुविधाएँ भी बढ़ रही हैं तथा व्यावसायिक बैंक सहायता के लिए भी धीरे-धीरे केन्द्रीय बैंक पर आश्रित होने लगे हैं। इससे आशा की जाती है कि इन देशों में भी साख-नियंत्रण के साधन के रूप में बैंक-दर की प्रयोग में वृद्धि होगी।

समाप्त